desirability of adopting a standard practice of specifying a single rate at which private' investors are asked to sell power. The Committee felt that adoption of a simple tariff system would also eliminate the need of offering guaranteed PLF linked return on equity.

(d) and (d) Setting up of private power projects normally comes under the realm of the State Governments. However, the Control Electricity Authority scruitinises the costs and tariffs of these projects and accords techno-economic clearance only when it is satisfied that the cost are reasonable.

बैंकों की रूग्ण उद्योगों में फंसी राशि

59. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीकृत बैंकों की बहुत बड़ी राशि देश के रूग्ण उद्योगों में फंसी हुई है,

(ख)यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान ऐसी कितनी-कितनी राशि अनुत्पादक कार्यों में फंसी हुई थी, और

(ग) अनुत्पादक क्षेत्र में फंसी हुई ऐसी राशि उपरोक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान उद्योग के विस्तार एंव विकास के प्रयोजनार्थ बैंकों द्वारा दी गई कुल राशि का कितना-कितना प्रतिशत थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.) देवी प्रसाद पाला) : (क) से (ग)भारतीर्य रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैकों से प्राप्त हुए छमाही आंकड़ों इकाइयों पर, देश में रूग्ण/कमजोर औद्योगिक इकाइयों पर बकाया राशि और मार्च 1992, मार्च, 1993 और मार्च 1994 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार, उद्योग को कुल बकाया बैंक ऋण की तुलना में ऐसे बकाया की प्रतिशतता, निम्नकार थी :

(करोड़ रूपए)

के अन्त की स्थिति	बकाया राशि	उद्योग को कुल बैंक ऋण की तुलना में बकाया राशि की प्रतिशतता
मार्च,1992	11533.30	17.6
मार्च,1993	13134.44	16.7
मार्च,1994	13695.74	17.0

काले धन की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होना

60. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** :

श्री अनन्तराय जायसवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में काले धन की मात्रा हजारों करोड़ रूपये में हैं और वह राशि निरन्तर बढ़ रही है,

(ख) यदि हां, तो काले धन की यह राशि कुल कितनी है और काले धन की उक्त राशि की मात्रा में ज्यादातर राशि किस धंधे से पैदा होती है,और

(ग) क्या सरकार ने देश में तीव्र गति से बढ़ रहे काले धन की मात्रा पर अंकुश/रोक लगाने हेतु कोई ठोस कार्रवाई की है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और उसका क्या परिणाम रहा है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रेशखर मूर्ति): (क)और (ख) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा 1983-84 में किए गए अध्ययन में 31584 करोड़ रू. से 36786 करोड़ रू. के बीच काले धन का अनुमान लगाया गया था । इसके बाद इस विषय पर कोई प्रमाणिक अध्ययन नहीं किया गया है और अत: काले धन की मात्रा को बनाना अथवा सर्वाधिक काले धन को पैदा करने वाले कारोबारों का पता लगाना संभव नहीं है ।

(ग) जी,हां । सरकार काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए समय-समय पर जैसा भी आवश्यक समझा जाए, आवश्यक कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती आ रही है । कराधान की दरों को

उत्तरोत्तरयुक्तिपूर्ण बनाया गया है । इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक ऐसे उपबंध है, जिनका उद्देश्य काले धन के पैदा होने को रोकना है । इसके अन्तर्गत अन्य के साथ-साथ धारा 44-क क और 44-क ख के अन्तर्गत उचित मामलों लेखों को अनिवार्य रूप से रखना और उनकी लेखा-परीक्षा, धारा 40-क(3), 269 ध ध और 269-न के अन्तर्गत नकद लेन-देनों पर प्रतिबंध, अध्याय ग के अन्तर्गत सम्पत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार खरीद से संबंधित उपबंध और कर चूककर्ताओं को दंड देने के लिए अर्थदंडों और अभियोजनों से संबधित उपबंध शामिल है । इस अधिनियम मे कर अपवचन का पता लगाने के लिए सम्मनों, सर्वेक्षणों और तलाशियों आदि से संबंधित उपबंध भी निहित है । उचित मामलों में इन उपबंधों का सहारा लिया जाता है । प्रतिवर्ष बढ़ता हुआ कर राजस्व इन उपायों की सफलता का संकेत देता है ।

रूपए के मूल्य में गिरावट आना

61. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेशी मुद्रा बाजार में अमरीकी डालर के मुकाबले भारतीय रूपए में निरन्तर आ रही गिरावट के संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं,

(ख) सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को किस तरह से दूर करने का विचार रखती है,

(ग) डालर के मुकाबले अन्य विकसित देशों की मुद्राओं एंव भारतीय रूपए में गिरावट का प्रतिशत क्या है,

(घ) क्या यह सच है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से रूपए के मूल्य में गिरावट हो रही है, और

(ड.) इस संबंध में तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसार पाल) : (क) हाल की अवधि में अवलोकित रूपए की विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता अव्यवहारिक कारणों से भी । भारतीय रिजर्व बैंक ने सट्टेबाज तत्वों की समाप्ति के लिए विदेशी मुद्रा बाजार के हाजिर और वायदा दोनों खंडों में हस्तक्षेप किया । इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने सट्टेबाजी का सामना करने के लिए 7.2.1996 को कुछ मजबूत उपायों की भी घोषणा की । इनमें ये शामिल हैः- (1) अमरीकी डालर में मूल्यवर्गित लदान-पश्च नियति ऋण संबंधी योजना का समापन (2) दिन से ऊपर के लिए लदान-पांच नियति रूपया ऋण पर ब्याज दर को मुक्त करना, (3) आयात वित्त पर ब्याज प्रभार में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करना, और (4) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वायदा संविदाओं को निरस्त करने और प्राधिकृत डीलरों के अंतः दिवसीय सौदों की मानीटरिंग । ये उपाय 8.2.1996 के प्रभावी हुए । इन उपायों की घोषणा के बाद से विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता आई है । रूपया-डालर दर में सुधार हो कर 23.2.1996 को यह 36.56 रूपए प्रति अमरीकी डालर हो गयी है । विनिमय दर गतिविधियों की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के द्वारा लगातार मानीटरिंग की जा रही है और जब कभी आवश्यक होगा मुद्रा दर में अत्यधिक अस्थिरता का सामना करने और सुव्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे ।

(ख)हाल के महीनों में रूपए की विनिमय दर में समस्त उतार-चढ़ाव सुदृढ़ प्रतिस्पर्धा पर आधारित व्यवहार्य भुगतान संतुलन के दीर्घावधिक उद्देश्यों के समनुरूप है ।

(ग) 31 मार्च, 1995 को प्रभावी दरों की तुलना में 16 फरवरी, 1996 को अमरीकी डालर की तुलना में रूपए और प्रमुख मुद्राओं के अवमूल्यन का विवरण नीचे दिया गया हैः-

मुद्रा	अवमूल्यन (-) अमरीकी डालर की तुलना में (प्रतिशत)
भारतीय रूपया	- 14.1
जापानी येन	- 17.7
पौंड स्टर्लिंग	- 4.3
डयूश मार्क	- 5.6
फ्रांसीसी फ्रांक	- 3.9

(घ) और (ड.) मार्च1993 और जुलाई 1995 के बीच दो वर्षों की अवधि में अमरीकी डालर की तुलना में रूपए की विनिमय दर स्थिर बनी रही । इस अवधि के दौरान भारत में मुद्रास्फीति की दर भारत के प्रमुख व्यापार भागीदार देशों में मुद्रास्फीति की दरों की तुलना में उच्च थी । भारत और विदेशों के बीच मुद्रास्फीति में इन अंतरों का तात्पर्य रूपए के विदेशी मूल्य में वास्तविक अधिमूल्यन और भारत की प्रतियोगितात्कता में क्षरण